कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qksu (dk-) : +91(11) 23381428

QSD : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

सरकार की उपलब्धियां : आम बजट 2016–17

बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती.................................. 6

संगठनात्मक गतिविधियां

भाजयुमो राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न.. 8

भाजपा अध्यक्ष का प्रवास : बहराइच (उत्तर प्रदेश).............................. 9

वैचारिकी

एकात्म मानववाद की अवधारणा

– **दत्तोपंत ठेंगड़ी**.. 11

श्रद्धांजलि

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार.. 13

आम बजट 2016–17

गांव, गरीब एवं किसान हितैषी बजट.. 14

लेख

झूठ के सहारे राजनीति

– **एम. वेंकय्या नायडु** 22

अन्य

रेल–बजट 2016–17.. 24

भाजपा रैली : आंध्र प्रदेश.. 27

बरेली (उप्र) में किसान रैली... 28

कार्यकर्ता सम्मेलन : गुजरात.. 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को गुढी पडवा की हार्दिक शुभकामनाएं!

फेसबुक

सोशल मीडिया से...

twitter

श्री नरेंद्र मोदी

उन सभी को, जो बापू के आह्वान और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर दांडी मार्च में शामिल हो गए, को सलाम।

.....

श्री अमित शाह

देशद्रोह को अभिव्यक्ति की आजादी के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, अगर राहुल इन राष्ट्रविरोधी नारों को आजादी की अभिव्यक्ति मानते हैं तो सोनिया गांधी और कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि वह इन नारों के साथ है क्या?

.....

श्री वेंकैया नायडू

कांग्रेस बताए कि 50 साल बाद के लंबे शासन के बाद भी लोग क्यों अभी भी निरक्षर हैं। कांग्रेस ने लोगों को साक्षर बनाने के लिए क्या कदम उठाए? ऐसा उन्होंने केवल 5 साल में नहीं, बल्कि 50 साल के लंबे शासन में किया, इस दौरान वे दिल्ली से गली और संसद से पंचायत तक सत्ता में थे। अब वे राजस्थान और हरियाणा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कानून बनाने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री नरेंद्र मोदी

@narendramodi

सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो... निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियां संसद में याद आईं।

.....

श्री अमित शाह

@AmitShah

फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना इत्यादि कार्यक्रम किसान हित में एतिहासिक कदम है।

.....

पाथेय

यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि पार्टी-संगठन कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता और न ही कभी ऐसा आभास होना चाहिए कि यह सरकार का हिस्सा बन गया है। सरकार को अपना काम करना है और हमें अपना काम करना है। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना होगा, किन्तु दोनों को कभी एक नहीं हो जाना चाहिए। अभी भी देश के ऐसे बहुत से विशाल क्षेत्र हैं, कुछ दूरदराज के और अन्य पास के, जहां हमें अभी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लोगों के बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जिनके पास हमें पहुंचना है और विश्व के बारे में उन्हें अपने सार्वभौमिक विचारों के बारे में विश्वस्त करना है। अनेक ऐसे काम हैं, जिनमें समाज-सुधार के काम भी शामिल हैं, जो अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, इसका क्षय नहीं करना है।

- कुशाभाऊ ठाकरे

समृद्ध गांव, खुशहाल किसान, विकसित भारत

संसद में प्रस्तुत 2016-17 के बजट की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इस प्रशंसा का प्रमुख कारण है कि अब तक सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में जो क्षेत्र सबसे अंतिम स्थान पर थे, अब सबसे ऊपर आ गये हैं। यह बहुत ही स्वागत योग्य है कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र अब सरकार की प्राथमिकताओं के केन्द्र में हैं। भारत किसानों का देश है और छह लाख के भी अधिक गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिये उठाये जा रहे कदम वास्तव में एक लंबी छलांग है। यह एक बड़ी चुनौती है परन्तु भारत का वास्तविक विकास इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करने में है। यह पहली बार है कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाकर करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया है। भाजपा के आर्थिक दर्शन के अनुरूप बजट 'अंत्योदय' एवं 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा से प्रेरित है। यह पहली बार है जब बजट से यह परिलक्षित हो रहा है कि भारत की समृद्धि का मार्ग किसानों के खेतों तथा गांवों के विकास से होकर निकलता है।

जबकि पूरा विश्व आर्थिक मंदी एवं अस्थिर बाजार की चुनौतियां झेल रहा है वैसे समय में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने ठीक वैसा ही बजट प्रस्तुत किया जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इतने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में भी श्री जेटली ने न केवल वित्तीय घाटा के लक्ष्य को प्राप्त किया बल्कि इसे और अधिक घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी राशि आवंटित की गई है। इन आवंटनों से भारत के भविष्य के प्रति दृष्टि स्पष्ट होती है। इससे सिंचाई सुविधाएं, ग्रामीण सड़क एवं अन्य संरचनाएं, 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप', मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे अभिनव प्रकल्पों द्वारा कृषि आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि बीमा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं से देश का आम आदमी स्वयं को मजबूत एवं सुरक्षित महसूस कर रहा है। बजट में प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित होगी तथा श्यामा प्रसाद मुकर्जी रूरबन मिशन से गांवों में अब शहरों जैसी सुविधायें उपलब्ध हो पायेंगी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी गांवों तक बिजली तथा चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता की योजनाओं से गांवों में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों के आय को दुगुना करने की घोषणा की है और यह बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

हर किसी ने बजट को गरीबों एवं किसानों का बजट बताया है। भारत का विकास गांवों के विकास में निहित है जहां देश की बहुसंख्यक जनता रहती है। अब तक के सरकारों का ध्यान शहरों पर रहा जिससे असमानता बढ़ी, गांव उपेक्षित हुए और किसान आत्महत्या को मजबूर हुए। कृषि, किसान एवं गांवों की उपेक्षा से खेती घाटे का सौदा बनकर रह गया जिससे लोग खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन को मजबूर हुए। यदि हम भारत को तेजी से विकास की ओर बढ़ते देखना चाहते हैं तब इस परिदृश्य को बदलना पड़ेगा तथा गरीबों, किसानों एवं गांवों के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। 'ट्रिकल डाउन' की नीतियों से गरीबों के चेहरों पर मुस्कान नहीं आ पाया अब विकास को गांवों से शुरू होना पड़ेगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश से न केवल करोड़ों चेहरों पर मुस्कान आयेगी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी तथा हम उच्च विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था तब ही रफ्तार पकड़ सकती है जब हम सबसे वंचित एवं उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण कर पायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र का क्रय शक्ति बढ़ाकर हम देश के सुनहरे भविष्य का खाका खींच सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि यह सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं वंचित वर्गों को समर्पित है इस बजट ने इस प्रतिबद्धता को पूरी तरह से वास्तविकता में बदल दिया है। ■

बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती, कृषि विकास और बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट की सराहना की और किसान, गरीब, पिछड़े और युवाओं के विकास एवं कल्याण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस वाले बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की ओर से बहुत - बहुत बधाई दी।

बजट का स्वागत करते हुए श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है जो गांव, गरीब और किसानों के विकास व कल्याण को केंद्र में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती, कृषि विकास और बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास में पिछड़ गए लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इस बजट का मुख्य उद्देश्य है।

कृषि एवं किसानों के कल्याण पर खास ध्यान

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केंद्र की भाजपा सरकार पहले दिन से ही कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है और उन्हें इनकम सिक्योरिटी देना चाहती है, जिसके लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना, आर्गेनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 'सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान' की दिशा में ठोस पहल करते हुए मोदी सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा को लागू कर दिया है जिसके लिए इस बजट में 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की कृषि भूमि के एक-एक इंच को सिंचाई हेतु पानी मुहैय्या कराने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाने का निर्णय लिया गया है जो देश में कृषि विकास को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि दालों की कीमतें कम करने के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई है और इसके बाजार स्थिरीकरण कोष के लिए 900 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो एक स्वागत योग्य कदम है। श्री शाह ने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित करने का जो निर्णय लिया गया है, वह किसानों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। यही नहीं, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खास जोर दिया गया है और इसके लिए 87,761 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाओं में लगभग 228 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों को 2.7 लाख करोड़ ग्राम पंचायतों के विकास के लिए हर ग्राम पंचायत को 80 लाख और छोटे कस्बों को संवारने के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जो देश की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले साल 5542 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई जो कि पिछले तीन वर्षों की कुल उपलब्धि से भी कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है।

युवाओं के सशक्तीकरण और रोजगार के लिए प्रतिबद्ध

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि

युवाओं के स्वरोजगार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना के तहत भुगतान लक्ष्य को बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जोकि एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत एससी - एसटी कैटगरी के युवाओं और महिलाओं को जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 76 लाख युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है जबकि सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देना है और इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि से देश भर में 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने का निश्चय किया गया है, यह भाजपा सरकार की युवाओं के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल की है जिसके अंतर्गत एक लाख रुपये तक की मेडिकल सुविधाएं दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि देश के गरीब लोगों तक सस्ती दवाइयां पहुंचाने के निश्चय को साकार करते हुए सरकार ने 3000 मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है जो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करते हुए देश के हरेक जिला अस्पतालों में नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम का एलान किया है ताकि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में छूट देने का निर्णय किया है जिनसे बुजुर्गों को काफी फायदा मिलेगा।

यह बजट देश को तरक्की की राह पर लाने और 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर चलकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी।

श्री शाह ने कहा कि गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के द्वारा स्वच्छ ईंधन देने का 2000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मोदी सरकार का एक कदम है जिससे देश के 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा।

श्री शाह ने कहा कि नए कर्मचारियों के लिए सरकार ने तीन वर्ष तक पीएफ देने का फैसला किया है जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

बुनियादी ढांचे का विकास

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने देश के हरेक हिस्से को एक साथ और एक सामान विकास हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2,21,246 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि देशभर में राजमार्गों का जाल बिछाने के लिए नेशनल हाइवेज को 10,000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज को 50 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 55000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, इसके साथ ही 160 हवाई अड्डों का भी विकास किया जाएगा ताकि हवाई यात्रा को और अधिक सुगम बनाया जा सके।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का यह बजट देश को तरक्की की राह पर लाने और 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर चलकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक सहज और निर्बाध गति से पहुंचेगी, कृषि विकास और किसानों का कल्याण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। भाजपा अध्यक्ष ने पुन: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को समर्पित आम बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को हार्दिक बधाई दी। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : भाजयुमो राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान

संवाददाता द्वारा

भारतीय जनता युवा मोर्चा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 6 मार्च तक मथुरा-वृंदावन के शांति सेवा धाम में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री ओम प्रकाश माथुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री श्रीकांत शर्मा उपस्थित थे।

बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गये। एक राजनीतिक और दूसरा इण्डिया फर्स्ट। राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री स्वदेश सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। भाजयुमो के राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार के गरीबोन्मुख और जनोन्मुख नीतियों की तारीफ की गई है।

इण्डिया फर्स्ट प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की आलोचना की गई है। सम्मेलन के सत्रों को केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया गया।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कृषि राज्यमंत्री श्री संजीव बालियान इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। सम्मेलन के दिन भाजयुमो की कार्यसमिति की भी बैठक हुई, जिसमें अतिथि के रूप में रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे उपस्थित थे। समापन सत्र को भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली तथा भाजपा महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल द्वारा सम्बोधित किया गया।

सम्मेलन ने राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज जारी रखने का प्रण किया गया। सम्मेलन के अंत में एक यात्रा का भी आयोजन किया गया।■

प्रदेश में समाजवादी सरकार से समाजवाद तो गायब है बस जातिवाद की सरकार बची हुई है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दिनांक 24 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में ग्यारहवीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद गाजी को उसके समस्त सेना सहित खत्म करनेवाले देश के महान सपूत राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया और इस उपलक्ष्य पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने देश के युवाओं से राजा सुहेलदेव के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हुए कहा कि जो अपने वीर पुरखों को याद नहीं करते, वह इतिहास नहीं बना सकते।

स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आड़ में देश में वोट बैंक की खातिर राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा देने की राजनीति पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में लग रहे 'भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी', 'भारत तेरे टुकड़े होंगें', 'अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे जातिल जिंदा हैं', 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे देश विरोधी नारों से क्या देश का कोई नागरिक सहमत हो सकता है? जवाब में सभा में उपस्थित विशाल जनसमुदाय ने एक स्वर में इन नारों की कड़ी भर्त्सना की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'देश की संसद सबसे बड़ी पंचायत है, वहां इस मुद्दे पर बहस होनी है, मैं सभी पार्टियों से मांग करता हूं कि वह स्पष्ट करें कि वह इन देशविरोधी नारों से समर्थन में हैं या विरोध में।' उन्होंने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि भारत की बर्बादी के लगाए गए नारे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है या फिर राष्ट्रद्रोह। श्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन राष्ट्र विरोधी नारों का विरोध करते हैं तो उन्हें वोट बैंक के लिए निचले स्तर की राजनीति का परित्याग करके सार्वजनिक रूप से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह देश अपने लाखों वीर सपूतों की कुर्बानी से आजाद हुआ है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को तोड़नेवाली ताकतों का समर्थन करने वालों को जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा, यह देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इन देशद्रोही नारों की कड़ी निंदा करती है और देश के संविधान और कानून के मुताबिक इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने उत्तर प्रदेश को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताते हुए कहा कि प्रदेश में विधान सभा चुनाव में तो अभी थोड़ा समय बाकी है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने राज्य में भाजपा की सरकार लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के कितने राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए कहां-से-कहां पहुंच गए लेकिन उत्तर प्रदेश भरपूर प्राकृतिक संसाधनों, मेहनतकश किसान और मेधावी छात्रों के बावजूद विकास के दौर में काफी पीछे छूट गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश श्री कल्याण सिंह और श्री राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ा था लेकिन पिछले 20 वर्षों से सपा और बसपा की जातिवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ने राज्य को तबाह करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सपा की सरकार आती है

तो गुंडागर्दी आती है और जब बसपा की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों आती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार से समाजवाद तो गायब है बस जातिवाद की सरकार बची हुई है। सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो हम राज्य के चप्पे-चप्पे का और हर घर का विकास करके दिखाएंगें।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोक सभा चुनावों में भाजपा को अपूर्व प्यार दिया और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की 'सबका साथ - सबका विकास' की नीति को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से लोक सभा चुनाव जीतकर श्री नरेन्द्र मोदी केंद्र की गरीबों की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, देश के गरीबों, गाँवों, किसानों, दलितों एवं पिछड़ों के कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना के माध्यम से 20 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए, मुद्रा बैंक के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार देने और स्वाबलंबी बनाने के लिए काफी आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराये गए, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा के माध्यम से 'सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान' की दिशा में ठोस पहल करते हुए किसानों को चतुर्दिश सुरक्षा कवच देने का अभिनव प्रयास किया गया, फसलों के नुकसान में मिलने वाले मुआवजे की राशि में बढ़ोत्तरी की गई और इसके पैमाने को बदला गया। स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के बड़े अवसर पैदा किये गए और ये सभी योजनाएँ देश के गरीबों, शोषितों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण को ही ध्यान में रखकर तैयार की गई। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अभी भी बिजली से वंचित रहे लगभग 20 हजार गांवों में से मात्र डेढ़ साल के कार्यकाल में ही मोदी सरकार द्वारा लगभग 6000 से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास का एक बड़ा अभियान चला है, भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा शासित राज्य विकास में देश के अन्य राज्यों से कहीं आगे हैं। नागरिकों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अव्वल हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई, जनता ने बार - बार भाजपा को राज्य की सत्ता की चाभी सौंपी, आप एक बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को लाइये, आपको सत्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, अब उत्तर प्रदेश के विकास पथ पर चलने की बारी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सपा-बसपा के छलावे से और जातिवादी राजनीति से बाहर आइये और भाजपा को चुनकर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करिये। उन्होंने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रदेश के हर तबके का सर्वांगीण विकास करके इसे उत्तम प्रदेश बनायेंगे।■

बलरामपुर में 'अटल भवन' भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने देश के प्रत्येक जिले में भाजपा कार्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देते हुए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिनांक 24 फरवरी 2016 को पार्टी कार्यालय 'अटल भवन' की आधारशिला रखी। ज्ञात हो कि बलरामपुर, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक यात्रा का प्रथम पड़ाव रहा है और उन्होंने लोकसभा का अपना पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर संसदीय सीट से ही लड़ा था। देश के प्रत्येक जिले में पार्टी कार्यालय की परिकल्पना भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह की ही सोच का परिणाम है। उनका मानना है कि प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आधुनिक कार्यालय होना चाहिए जो प्रेस कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी तमाम सुविधाओं से सुसज्जित हो ताकि पार्टी आसानी से देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके और उनके विकास और कल्याण के मुद्दों को हल कर सके, साथ ही उन्हें न्याय दिला सके। पार्टी का जिला कार्यालय अपने कार्यकर्ताओं से भी सहज तरीके से संवाद स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। ■

एकात्म मानववाद की अवधारणा

– दत्तोपंत ठेंगड़ी

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय मौलिक विचारक थे। उन्होंने 1965 में भारतीय संस्कृति पर आधारित 'एकात्म मानववाद' प्रस्तुत किया। 'एकात्म मानववाद' भाजपा का मूल दर्शन है। हम यहां राष्ट्रवादी विचारक स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा 'एकात्म मानववाद की अवधारणा' पर प्रस्तुत विचार प्रकाशित कर रहे हैं :-

भारत में कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई द्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई ईश्वरवादी है, कोई अनीश्वरवादी है, कोई मूर्तिपूजक है, कोई निराकार की उपासना करता है और सभी इसी परम्परा के हैं, सभी इसी रचना के अंगभूत हैं। ईश्वरवादी हैं, तो वे भी कितने हैं, जितने आदमी उतने देवता। यहां 33 करोड़ देवता हैं। मानो जिस समय 33 करोड़ की कल्पना की गयी, उस समय हमारी जनसंख्या 33 करोड़ रही होगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसकी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार अलग-अलग मार्ग होंगे। पश्चिम में वैचारिक आबद्धता है। हमारे मार्ग से ही भगवत् प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जहां सोचने का अभ्यास है, वहां यह लगना अस्वाभाविक नहीं कि भारत में कितना परस्पर विरोध है। कोई आस्तिकता की बात करता है, और कोई नास्तिकता की बात करता है। यह सब उनको विचित्र लगता है। इसी भांति व्यक्ति की दृष्टि से परिवार, राष्ट्र, समाज, अन्तर्राष्ट्रीयता आदि की जो भूमिकायें हमारे यहां हैं, उनमें भी अन्तर्विरोध दिखाई देता है।

अपने यहां यह माना गया है कि व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होना चाहिये, अत: इस तरह की सामाजिक, आर्थिक रचना होनी चाहिये, जिससे सम्पूर्ण सुख और विकास प्राप्त हो सके। इसी नाते व्यक्ति को मान्यता देने के साथ-साथ परिवार को भी मान्यता दी गयी है। ''मातृ देवो भव'' कहा गया है। यह नहीं कहा गया है कि व्यक्ति को मान्यता दी गयी है, इसलिये शादी के बाद पत्नी को लेकर और परिवार, दोनों को मान्यता देकर उनका अपना- अपना स्थान बताया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि, ''त्यजेदेक कुलस्यार्थे'' - कुल के लिये एक व्यक्ति का त्याग किया जाये, वह आत्मनाश करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि, ''आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत'' आत्मा के लिये कुल को, सम्पूर्ण पृथ्वी को छोड़ दो। पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों को इसमें बड़ा अन्तर्विरोध दिखता है। लेकिन वह नहीं है, यह हम सभी जानते हैं।

व्यक्ति और समाज-यह स्थिति राष्ट्रीय समाज और व्यक्ति की अपने यहां है। पश्चिम में इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष है। वहां यह समस्या उग्र हो उठी कि व्यक्ति और समाज का दायरा, उसकी मर्यादा क्या हो, यदि व्यक्ति का दायरा बड़ा होगा तो समाज की मर्यादा उसी मात्रा में होगी और यदि समाज का दायरा बड़ा होगा तो उसी मात्रा में व्यक्ति की मर्यादा, उसका दायरा छोटा हो जायेगा। इस तरह पश्चिमी देशों में दोनों के बीच रस्साकशी चल रही है।

भारत में व्यक्ति को भी मान्यता है और समाज को भी। दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं। जहां यह सिद्धान्त माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और सम्पूर्ण विकास प्राप्त हो- इस तरह की पूरी सुविधा समाज को देनी चाहिये- वहां यह भी माना गया कि समाज का अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। प्रत्येक व्यक्ति एक ओर अपने सुख और विकास की ओर बढ़े और दूसरी ओर स्वेच्छा से स्वयं को समाजाभिमुख समाज-केन्द्रित एवं समाज-समर्पित करें। अपने परिपक्व सुख और परिपक्व विकास को समाज पुरुष के चरणों पर अर्पित करे। इस प्रकार अपने यहां व्यक्ति स्वातन्त्र्य एवं सामाजिक अनुशासन में पूर्ण तादात्म्य दिखाई देता है। यद्यपि पश्चिम को इस पर आश्चर्य होता है।

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता-यही बात राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की भी है। पश्चिम में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का जन्म प्रतिक्रिया से हुआ। अत: दो देशों की राष्ट्रीयताओं में एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं हो पाता और अन्तर्राष्ट्रीयता का तालमेल राष्ट्रीयता के साथ सम्भव नहीं होता। हमारे यहां एक राष्ट्रवादी प्रार्थना है:

प्रादुर्भूत: सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे-मुझे सुख और कीर्ति दो, क्योंकि मेरा राष्ट्र अच्छा है। आगे सम्पूर्ण विश्व के लिये भी शुभ कामनायें हमारी प्रार्थना में मिलती हैं। मुझे स्मरण है जब

विश्व हिन्दू परिषद का अधिवेशन चल रहा था तो प्रश्न उठा कि हिंदू की परिभाषा क्या होगी? मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। किन्तु उसमें एक पहलू यह था कि हिन्दू को राष्ट्रीय माना जाये या अन्तर्राष्ट्रीय या वह उससे भी ऊपर है? उसकी परिभाषा कैसी की जाये? इसका उत्तर यह दिया गया कि जिस समय सम्पूर्ण संसार असंस्कृत था, हम ही केवल संस्कृतज्ञ थे। उस समय हिन्दू राष्ट्रवाद जग की संस्कृति है तो सबको संस्कारित करेंगे, उनके स्तर को ऊंचा उठायेंगे, यह हमारा अन्तर्राष्ट्रीयता में विरोध न होकर वह अन्तर्राष्ट्रीयता का आधार बन जाता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय है इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय न हो, और अन्तर्राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय न हो, ऐसा हमारे यहां नहीं दिखता। पश्चिम के लोगों को यह बड़ा विचित्र लगता होगा। वे कहते हैं कि परस्पर विरोधी बातें कैसे करते हो, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों कैसे हो सकता है? किन्तु इस विचार में विरोधाभास नहीं है, यह हम देख चुके हैं।

मानवता से भी आगे का विचार-अब इसके बाद जो धारणा आती है, पश्चिम के लोग तो उस पर विचार करते नहीं। वे अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीयता या मानवतावादी हैं। अपने यहां मानवता से भी ऊपर विचार किया गया है। मानवेतर सृष्टि की मान्यता अपने ही देश में है। मछलियों, गायों, चीटियों आदि का भरण-पोषण और उनको अपने ही समान मानने वाले लोग यहां हैं। उनको भी चीनी, आटा देने वाले लोग यहां हैं। इतना ही नहीं, जो देखने में निर्जीव सृष्टि है, उसको भी अपना एक अंग मानकर, उसमें भी भगवान का अस्तित्व है, ऐसी समझ अपने देश में है। आगे चलकर

मानवता से भी आगे का विचार-अब इसके बाद जो धारणा आती है, पश्चिम के लोग तो उस पर विचार करते नहीं। वे अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीयता या मानवतावादी हैं। अपने यहां मानवता से भी ऊपर विचार किया गया है। मानवेतर सृष्टि की मान्यता अपने ही देश में है।

ऐसा भी साक्षात्कार अपने यहां के लोगों ने किया है कि मनुष्य क्या है? मानवेतर प्राणी क्या है? यह जो अस्तित्व है- सारी सृष्टि है, वह एक ही है। पर एकता और एकरूपता इन दोनों में अन्तर है। सब एकरूप हैं, यह अपने यहां नहीं कहा गया। लेकिन यह अवश्य कहा गया कि सब मिलकर एक हैं और वह एकता कितनी दृढ़ है इसको यदि अच्छी तरह बताना हो तो ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म'' कहा जा सकता है। सम्पूर्ण सृष्टि को धारण करने की क्षमता अपने देश में है। ऐसा कुछ नियम है। जो सनातन और चिरन्तन है, अत: अपरिवर्तनीय हैं। उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं के आधार पर बदलती हुई परिस्थितियों में देश, काल, परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील रचनाओं का उद्घोष करने वाला धर्म हमारे यहां है। कितनी ही परस्पर विरोधी बातें हों, उनमें सामंजस्य हुआ है। यदि एक-एक सूत्र पर विचार करें तो परस्पर बहुत विरोधी बातें दिखाई देती हैं। कहीं कहते है कि कर्म करो, कहीं कहते हैं संन्यास लो। कभी कहते हैं कि जो कुछ है वह मोक्ष है- फिर कहते हैं कि जो कुछ है, सब व्यर्थ है। कभी कहते हैं कि - ''धर्मस्यमूलं अर्थ:''। किन्तु इन सबमें सामंजस्य ही नहीं तो इससे बढ़कर समन्वयात्मक पद्धति का निर्माण और इससे भी ऊपर जिसे सहज बुद्धि से समझा नहीं जा सकता और जो अपनी अक्षमता है- इस प्रकार की चुनौती देने वाला धर्म अपने यहां विकसित हुआ है। स्वामी विवेकानन्द के कथन को प्रमाण मानकर इस धर्म के विषय में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें समाज को धारण करने की क्षमता है। हजारों साल तक समाज की धारणा इससे हुई है। यह बात ठीक है कि पिछले बारह-तेरह सौ वर्षों मे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समाज की रचना में कौन-कौन से परिवर्तन होने चाहिये, इस पर विचार नहीं हुआ। इस परिवर्तन शब्द से चौंकने की जरूरत नहीं। क्योंकि ऐसे परिवर्तन समाज में समय-समय पर विशुद्ध दर्शन एवं धर्म के आधार पर होते ही रहे। जैसा कि हमारे यहां कहा गया है कि ''वेदा: विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना: नैको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम्'' अर्थात् वेद विभिन्न है, स्मृतियां भी विभिन्न है, और एक भी मुनि ऐसा नहीं हैं, जिसके वचनों को प्रमाण माना जाये। इस तरह के परिवर्तन करने के लिये जो शान्ति का समय चाहिये था वह बारह-तेरह सौ वर्षों में अपने यहां अवश्य उत्पन्न हुये हैं। किन्तु इन विकृतियों का ऑपरेशन किया जा सकता है जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि ''रोग का निदान करो किन्तु रोगी को समाप्त न करो।'' जो मूल रचना है, वह निर्दोष है। जो विकृति आ गयी है उसका ऑपरेशन कर दीजिये किन्तु व्यवस्था को कायम रखिये। इसी भांति समाज की धारणा सहस्रों वर्षों से बराबर चली आ रही है। अपरिवर्तनशील सनातन नियम तथा परिवर्तनशील रचना, इस प्रकार का मेल अपने यहां रहा।

...क्रमश:

श्रद्धांजलि

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार

शत्-शत् नमन

(1 अप्रैल 1889-21 जून 1940)

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल, 1889 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नए-साल के रूप में मनाए जाने वाले पर्व गुडी पड़वा के दिन जन्मे डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार महाराष्ट्र के देशस्थ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। डॉ. हेडगेवार की प्रारंभिक शिक्षा उनके बड़े भाई द्वारा प्रदान की गई। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉ. हेडगेवार ने चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाने का निर्णय किया। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी डॉ. बी. एस. मुंजू ने हेडगेवार को चिकित्सा अध्ययन के लिए 1910 में कोलकाता भेजा था।

वहां रहते हुए डॉ. हेडगेवार ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखीं। अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वह राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशब चक्रवर्ती के छद्म नाम का सहारा लेकर डॉ. हेडगेवार ने काकोरी कांड में भी भागीदारी निभाई थी। जिसके बाद वह भूमिगत हो गए थे।

इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉ. हेडगेवार ने यह बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने ही सुदृढ क्यों न हों, लेकिन फिर भी

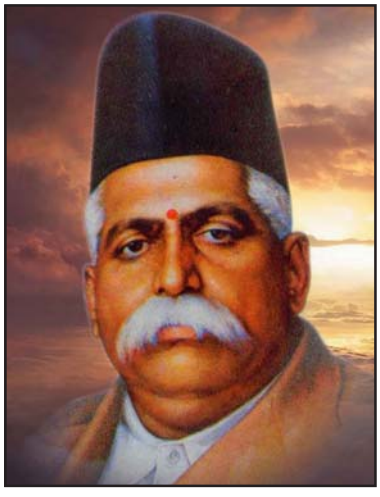

भारत जैसे देश में एक सशस्त्र विद्रोह करना संभव नहीं है। इसीलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलनों से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉ. हेडगेवार समाज सेवा और तिलक के साथ कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे। कांग्रेस में रहते हुए वह डॉ. मुंजे के और नजदीक आ गए थे जो जल्द ही डॉ. हेडगेवार को हिंदू दर्शनशास्त्र में मार्गदर्शन देने लगे थे। वे सन् 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ गये। वहाँ संयुक्त प्रान्त (वर्तमान यू.पी.) की युवा टोली के सम्पर्क में आये। बाद में आपका कांग्रेस से मोहभंग हो गया।

लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद डॉ. हेडगेवार कांग्रेस और हिन्दू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधीजी के अहिंसक असहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में भाग लिया, परन्तु खिलाफत आंदोलन की जमकर आलोचना की। ये गिरफ्तार भी हुए और सन् 1922 में जेल से छूटे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना

स्वाधीनता आदोलन में डा. हेडगेवार की भागीदारी की अनेक रूप एवं घटनाएं हैं, परंतु उनकी गतिविधियां एवं चिंतन राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रश्न तक सीमित नहीं थीं। एक प्राचीन भारतीय राष्ट्र का पराभव क्यों हुआ और इसे सबल एव संगठित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है-इन प्रश्नों का समाधान एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में वह जीवनपर्यत ढूंढते रहे तथा उनका निष्कर्ष था कि राष्ट्र के हित, पुनर्निर्माण एवं संगठन के लिए किया गया कार्य ईश्वरीय कार्य होता है।

उन्होंने 1925 में इसी ध्येय को अपने समक्ष रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना उन्होंने नागपुर की वीरान, बंजर एवं उपेक्षित भूमि मोहितेवाड़ा से की थी और देखते-देखते संघ सभी प्रांतों में फैल गया।

उन्होंने संगठन, समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि संघ की स्थापना, विस्तार एवं प्रभाव के पीछे प्रेरणा-पुरुष होते हुए भी वह सदैव सामने आने में संकोच करते रहते थे।

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एव स्वार्थ से मुक्त रहकर सार्वजनिक जीवन जीने का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। 21 जून, 1940 को टाइफॉयड के कारण डॉ. का निधन हो गया। ■

गांव, गरीब एवं किसान हितैषी बजट

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी 2016 को आम बजट (2016-17) प्रस्तुत किया। इस बजट की खासियत रही कि इसमें किसान, गरीब, पिछड़े और युवाओं के विकास एवं कल्याण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है।

कृषि एवं किसानों के कल्याण पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित

- किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी की जायेगी।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा शुरू की जायेगी।
- 89 सिंचाई परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया जायेगा, जिनके लिए अगले पांच वर्षों के दौरान 86,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इनमें से 23 परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा किया जायेगा।
- नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाया जायेगा।
- सिंचाई पर बाजार उधारी सहित कुल परिव्यय 12,157 करोड़ रुपये है।
- 6,000 करोड़ रुपये की लागत पर बहुपक्षीय वित्त पोषण के साथ सतत भूजल प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है।
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों एवं कुओं तथा जैविक उर्वरक के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण किया जायेगा।
- मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाएंगे।
- मृदा एवं बीज परीक्षण की सुविधाओं के साथ उर्वरक कंपनियों के 2,000 आदर्श खुदरा केन्द्र अगले तीन वर्षों के दौरान खोले जाएंगे।
- एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेटफॉर्म को 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन पर राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा।
- वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें राज्य का हिस्सा भी शामिल है। पीएमजीएसवाई को पूरा करने की लक्षित अवधि को दो साल घटाकर वर्ष 2019 कर दिया गया है, जबकि पहले इसे वर्ष 2021 तक

वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि पर कर प्रस्ताव वापस लिया

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) की निकासी पर कर लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया। श्री जेटली ने (लोकसभा में दिए गए एक बयान में) कर्मचारी भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति योजनाओं में कर लाभ के लिए योगदान पर 1.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा लगाने के प्रस्ताव को भी वापस ले लिया है। जेटली ने हालांकि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट और कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों को यथावत रखा। श्री जेटली ने कहा कि इन विषयों पर जो ज्ञापन मिले हैं उनको देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करना चाहेगी इसलिए मैं अपने बजट भाषण का 138वें और 139वें पैरे में पेश प्रस्तावों को वापस लेता हूं। एनपीएस के अंशदाताओं को निकासी पर 40 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव बरकरार है। गौरतलब है कि श्री जेटली ने 2016-17 के बजट प्रस्ताव में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि की कुल राशि के 60 प्रतिशत निकालने पर कर लगाने की बात कही थी। कराधान प्रस्ताव का औचित्य बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि कर्मचारियों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे कहां निवेश करें। सैद्धांतिक रूप से ऐसी स्वतंत्रता अनिवार्य है लेकिन सरकार के लिए कराधान से संबद्ध उद्देश्य को भी हासिल करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वरुप में नीतिगत उद्देश्य अधिक राजस्व प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पूरा करना था।

- वर्ष 2016-17 में नौ लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में प्रदान किये जाएंगे।
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अनाजों की ऑनलाइन खरीदारी करेगा। इसके तहत समुचित पंजीकरण और खरीद की निगरानी करने से पारदर्शिता आयेगी और किसानों को सहूलियत होगी।
- पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 'पशुधन संजीवनी' शुरू किया जायेगा। 'नकुल स्वास्थ्य पत्र' जारी किये जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र

- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति ग्राम पंचायत 81 लाख रुपए एवं प्रति नगरपालिका 21 करोड़ रुपए अनुदान सहायता दी जाएगी।
- सूखाग्रस्त एवं ग्रामीण समस्याग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक प्रखंड को दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत सहायता दी जाएगी।
- 300 रुरबन कलस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों को सहायता देंगे।
- सभी गांवों में 1 मई 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।
- अगले 3 वर्षों में लगभग 6 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए ग्रामीण भारत के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- संशोधित राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्डों कार्यक्रम के जरिए भूमि रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।
- सरकारी सब्सिडियों एवं लाभों की लक्षित आपूर्ति जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गरीबों एवं हकदारों तक पहुंच सकें।
- आधार संरचना का उपयोग करते हुए वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों आदि की लक्षित आपूर्ति के लिए नया कानून।
- उर्वरक में डीबीटी को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।
- देश में कुल 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख दुकानों को मार्च 2017 तक ऑटोमेट किया जाएगा।

मुद्रा

- 2016-17 में 1,80,000 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य।

सामाजिक क्षेत्र

- गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए व्यापक अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 2016-17 में 1.5 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए यह योजना 2 वर्ष और जारी रहेगी। परिवार की महिला सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे।
- नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रति परिवार 1 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30 हजार रुपए तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान किए जाएंगे।
- 2016-17 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाएंगे।
- राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। डायलिसिस उपकरणों के कुछ विशेष हिस्सों को कर छूट दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए एक नई आर्थिक प्रणाली का गठन किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय में एससी/एसटी हब का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा

- जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां पर 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
- विश्वस्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 10-10 संस्थानों को एक सक्षमकारी नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।
- एक हजार करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मार्क्स-शीट, पुरस्कारों इत्यादि के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की स्थापना की जायेगी।

कौशल

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।
- उद्योग जगत एवं शिक्षाविदों के साथ भागीदारी कर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड स्थापित किया जायेगा।
- ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिये 2200 कॉलेजों,

300 स्कूलों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

रोजगार सृजन

- भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 8.33 प्रतिशत का ईपीएस अंशदान अदा करेगी। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए को संशोधित किया जा रहा है, ताकि रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ सके।
- राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म के साथ राज्य रोजगार कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।
- छोटी एवं मझोली दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह में सातों दिन खुले रखने की इजाजत दी जायेगी।
- रिटेल क्षेत्र में नये रोजगार।

बुनियादी ढांचा, निवेश, बैंकिंग, बीमा इत्यादि क्षेत्रों में उपाय

- वर्ष 2016-17 में सड़कों और रेलवे के पूंजीगत व्यय पर 2,18,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसमें शामिल हैं-
- पीएमजीएसवाई के लिए 27000 करोड़ रुपये
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 55,000 करोड़ रुपये
- एनएचएआई बांडों के लिए 15,000 करोड़ रुपये
- रेलवे के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये
- बगैर उपयोग एवं कम इस्तेमाल वाली हवाई पट्टियों को एएआई बहाल करेगा और इसमें राज्य सरकारों के साथ भी भागीदारी होगी।
- परमिट प्रणाली को समाप्त कर सड़क परिवहन क्षेत्र (यात्री खंड) को खोला जाएगा। इससे गरीब एवं मध्यम वर्ग लाभान्वित होंगे, नये निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा एवं नये रोजगार सृजित होंगे। यह एक प्रमुख सुधार है।
- बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जन उपयोगिता (विवादों का निपटारा) विधेयक पेश किया जायेगा और पारदर्शिता से समझौता किये बगैर पीपीपी करारों पर नये सिरे से बातचीत के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- एफडीआई नीति में बदलाव।
- किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ नए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
- रणनीतिक विनिवेश के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है और

बजट में किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यानः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को लेकर वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की प्रशंसा की। श्री मोदी ने वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मैं वित्त मंत्री को खेती, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि चूल्हे पर खाना बनाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो गरीब महिला चूल्हे पर खाना बनाती है उनके भीतर 400 सिगरेट का धुंआ भर जाता है। ग्रामीण इलाकों के 5 करोड़ परिवार अब चूल्हे से मुक्ति पा सकेंगे। हमारी सरकार ने उन्हें फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने बजट को सपनों के करीब बताया और कहा कि अब तक सरकारें प्राथमिक शिक्षा के प्रचार पर ध्यान देती थीं लेकिन हमने बेहतर शिक्षा पर ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 तक हर गांव में बिजली होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और सामान्य मानव के जीवन में बदलाव होगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट में टैक्स की जटिलताओं को सरल बनाया गया है। साथ ही बजट में सेना और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। युवाओं के विकास के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने का मकसद है। इससे हमारी सीमाओं पर तैनात जवानों को भी फायदा होगा।

उनकी जल्द ही घोषणा की जाएगी।

- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निजी इकाइयों का नई परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विनिवेश किया जा सकता है।
- वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय कंपनियों के वियोजन पर एक व्यापक कोड को अधिनियमित किया जाएगा। बैंक दिवालिया और दिवालियापन कानून के साथ इस कोड से बड़ा क्रमबद्ध खाली स्थान की भरपाई होगी। यह एक बड़ा सुधार करने वाला कदम है।
- परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए सारफेसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इससे बैंक को विवादित परिसंपत्तियों से निपटने में मदद मिलेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों-(ए) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनः पूंजीकरण, (बी) सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की मजबूती के लिए रोड़ मैप की घोषणा की जाएगी, (सी) आईडीबीआई बैंक में सरकार की इक्विटी को 49 प्रतिशत को घटाने पर विचार, (डी) न्यायालय के मामलों की कम्प्युटरीकृत प्रोसेसिंग के साथ डीआरटी को मजबूत किया जाएगा।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और निपुणता में सुधार लाने के लिए सामान्य बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- गैर-कानूनी जमावर्ती योजनाओं से निपटने के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून तैयार किया जाएगा।
- राज्यों और जिलों को जोड़ने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का शुभारंभ किया जाएगा।
- वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीदारी के लिए डीजीएसएंडडी द्वारा प्रौद्योगिकीजन्य मंच स्थापित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता और निपुणता में सुधार के साथ-साथ खरीदारी की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।

वित्तीय विधा

- वर्ष 2016-17 में वित्तीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 प्रतिशत।
- एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन
- 2017-18 से गैर-योजना वर्गीकरण को हटाना
- केन्द्रीय योजना स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना। केन्द्रीय योजना के तहत 1500 से ज्यादा स्कीमों को तकरीबन 300 केन्द्रीय क्षेत्र और 30 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पुनर्गठित किया गया है।

सस्ते आवास को बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्गमीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोजना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से सौ प्रतिशत कटौती देने का प्रस्ताव किया। हालांकि इन उपक्रमों पर न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा।

पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपये तक के ऋणों हेतु 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव किया, बशर्ते मकान की कीमत इन रुपये से ज्यादा न हो।

श्री जेटली ने सरकारी-निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवाकर से छूट देने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए समय पर उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिए जाने का प्रस्ताव किया।

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी

एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेटफॉर्म इस वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा से और आगे बढ़ने तथा हमारे किसानों में आय सुरक्षा की भावना भरने का इरादा रखती है। इस संदर्भ में, सरकार की योजना किसानों की आय दोगुनी करने की है। उन्होंने कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की समस्या को दूर करने, सिंचाई के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, उर्वरक के संतुलित उपयोग के साथ मृदा उर्वरता को संरक्षित करने एवं कृषि से बाजार तक संपर्क मुहैया कराने का है।

श्री अरुण जेटली ने कहा कि 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध

खेती वाले क्षेत्रों में से केवल 65 मिलियन हेक्टेयर ही सिंचित हैं। इस बारे में, उन्होंने 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' की घोषणा की, जिससे कि अन्य 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के साथ लाने के लिए मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एआईबीपी के तहत 89 परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया जाएगा जो अन्य 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाने में मदद करेगा। उन्होंने इन परियोजनाओं में से 23 को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा करने का वादा किया। इन परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष 17 हजार करोड़ रुपए और अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्पस राशि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई निधि बनाई जाएगी। बहुपक्षीय वित्त पोषण के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूजल संसाधनों के ठोस प्रबंधन के लिए एक ऐसे ही कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्री जेटली ने मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों के कवरेज के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यह किसानों को उर्वरक का उचित उपयोग करने में सहायक होगा।

उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा विक्रय केंद्रों को अगले तीन वर्षों में मृदा एवं बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने जैव खेती के तहत 5 लाख एकड़ वर्षा जल क्षेत्रों को लाने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' की घोषणा की। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'जैव मूल्य शृंखला विकास योजना' प्रारंभ की जिससे कि उनके जैव उत्पादों को घरेलू एवं निर्यात बाजार प्राप्त हो सके। इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिवस पर एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के शेष 65 हजार गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2021 से बढ़ाकर 2019 कर दिया जाएगा।

गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन

वित्त मंत्री ने गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, इस योजना से चालू वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र स्थापित किया जाएगा। 2.5 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों की भलाई के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना बनाई गई है। सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इससे वर्ष 2016-17 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस कदम से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इससे खाना बनाने की आपूर्ति शृंखला में ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे।

जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में फिर से तेजी लाएंगे और 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने एक 'राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए राशि पीपीपी मॉडल के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जा सके।

1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, बजट 2016-17 में 1700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाया जाएगा तथा राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकार ने देश भर में 15,00 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का फैसला किया है, इसके लिए वर्ष 2016-17 के आम बजट में 17,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2,21,246 करोड़

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि बुनियादी ढांचा और निवेश बजट विषय 'ट्रांसफॉर्म इंडिया' का पांचवां सहायक स्तंभ है। 2016-17 में सड़क और रेलवे के परिव्यय पर कुल 2,18,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 27,000 करोड़ रुपये के आबंटन और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के लिए 55,000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। अन्य 15,000 करोड़ रुपये बॉन्ड के जरिए एनएचएआई द्वारा लगाए जाएंगे। रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

श्री जेटली ने घोषणा की कि 2016-17 में तकरीबन 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त करीब 50,000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। बजटीय अनुमान 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल 2,21,246 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और यात्री सड़क-परिवहन क्षेत्रों को यात्री खंड में खोलेगी। राज्यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उन्हें नए विधिक ढांचे को अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। उद्यमी कार्यदक्षता और सुरक्षा मानदंडों का पालन कर विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा तथा नए निवेश, रोजगार पैदा करने तथा स्टार्ट-अप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तमंत्री ने कहा, ''हम देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग के कार्य में तेजी लाई जा रही है और इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।'' नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा असेवित और अल्पसेवित विमानपत्तनों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी भी की जा रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तीन विशिष्ट पहलों की घोषणा

श्री जेटली ने सभी किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तीन विशिष्ट पहलों की घोषणा की, जिसमें खरीदारी का विकेन्द्रीकरण, एफसीआई के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी प्रणाली और दालों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध करना शामिल है। वित्त मंत्री ने दुग्ध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई-पशुधन हॉट और देसी नस्लों के लिए राष्ट्रीय जीनोमिक केन्द्र की स्थापना करने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं में अगले कुछ वर्षों के दौरान 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

श्री जेटली ने ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ग्रांट इन एड के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। ऐसा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया है और यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। दीन दयाल अंत्योदय मिशन को प्रत्येक सूखाग्रस्त विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा।

श्री जेटली ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्टरों को विकसित करने की भी घोषणा की। उन्होंने 01 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। पंचायती राज संस्थानों की मदद के लिए उन्होंने नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का भी प्रस्ताव किया है।

वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय

अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्टार्ट अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

वित्त मंत्री ने अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्स को पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर सौ प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा। यदि विनियमित/अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्ट अप

में निवेश किया गया हो, जिनमें उनकी अधिसंख्य शेयरधारिता हो।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है और नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। श्री जेटली ने पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का भी प्रस्ताव किया जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में दीर्घावधिक पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के संबंध में अपनी आय की पांच प्रतिशत कटौती की पात्र होंगी। उन्होंने विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्थान के आधार पर रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष आस्थगित रखने का भी प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री ने 75 लाख मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी है।

उन्होंने कहा कि ओईसीडी और जी-20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक 2016 में, 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है।

उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं को सेवा से छूट देने का प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री ने ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गयी 'निरामय ' स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गयी साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास, सहायक सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर शून्य बुनियादी सीमा शुल्क लगता है। उन्होंने ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव भी किया।

छोटे करदाताओं और अन्य के लिए कर में राहत की घोषणा

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के पास गरीबी और असमानता दूर करने के लिए कराधान प्रमुख साधन है और इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, लेकिन वे छोटे करदाताओं को राहत देना चाहते हैं। इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 87-ए के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को 3000 रुपये की राहत मिलेगी। धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी।

आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के तहत टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है, जिसका लाभ लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को मिलेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को विस्तृत बही खातों के रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी। अनुमानित कराधान योजना को ऐसे व्यवसायियों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी अनुमानित 50 प्रतिशत की प्राप्तियों के साथ सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये की हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति की उद्योगों में बेहतर भागीदारी

श्री अरुण जेटली ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि उद्योग संघों की भागीदारी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की भागीदारी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। यह केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की खरीदारी नीति 2012 के अधीन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वैश्विक सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि अपनाने और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए पेशेवर मदद उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा

स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी देने की भी घोषणा की और बताया कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये हैं।

इस योजना से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक उद्यमी के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इस योजना से कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और कौशल विकास के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद योजना को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाएगा।

युवाओं के लिए सौगात: स्किल इंडिया मिशन

वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य मानव आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान की शुरूआत से ही एक विस्तृत कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। श्री जेटली ने अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव भी किया।

वित्त मंत्री ने उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनाने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों, खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ा जाएगा।

श्री जेटली ने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरूआती तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का योगदान करेगी। यह स्कीम 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वित्त विधेयक 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80 जे जे ए ए के अधीन उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। श्री जेटली ने कहा कि जुलाई 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा भी प्रारम्भ की गयी थी। रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग पहले से ही इस सेवा में पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव किया। श्री जेटली ने राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रावधान किया। ■

असम में भाजपा-अगप के बीच चुनावी समझौता

असम में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए आगामी असम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समझौते के अनुसार, असम के 24 विधान सभा सीटों पर असम गण परिषद चुनाव लड़ेगी। जिन 24 विधान सभा सीटों पर असम गण परिषद चुनाव लड़ेगी, वह इस प्रकार हैं: नहरकटिया, अमगुड़ी, टियोक, डेरगांव, बोकाखाट, सरुपाथर, कलियाबर, बरहामपुर, वेस्ट गुवाहाटी, चायगांव, बोको, बोंगाईगांव, साउथ अभयपुरी, नार्थ अभयपुरी, बरपेटा, पतचरकूची, कमलपुर, तेजपुर, नार्थ लखीमपुर, जमुना मुख, लाहोरी घाट, वेस्ट बिलासीपारा, सरूखेतरी और डलगांव। इस आशय की घोषणा केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में की। इस अवसर पर बोलते हुए असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री अतुल बोरा ने कहा कि राज्य का विकास और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र में विश्वास करते हुए असम की जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार व प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्वानंद सोनोवाल, भाजपा के प्रदेश चुनाव संयोजक श्री हेमंत विश्व शर्मा और असम गण परिषद के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महंता भी उपस्थित थे। ■

झूठ के सहारे राजनीति

वेंकैया नायडू

कांग्रेस और वामदल युवा रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू में लगे देशविरोधी नारे की घटना को न सिर्फ अपने लिए राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस पर क्षुद्र राजनीति भी कर रहे हैं। वे राजग सरकार को बदनाम करने के लिए द्वेषपूर्ण और झूठा अभियान चला रहे हैं और इस क्रम विश्वविद्यालयों को भी नहीं बख्श रहे हैं। हालांकि वे अपनी इस कुटिल योजना में सफल नहीं हो पाए हैं और छात्रों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की बड़ी आबादी को अपने इरादों से प्रभावित नहीं कर सके हैं। विश्वविद्यालयों की बदहाली के जिम्मेदार कारकों और भारत की एकता-अखंडता की चुनौतियों पर चर्चा करने के बजाय ये दल गैरजिम्मेदार और निंदनीय तरीके से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय में देशविरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में बिना सोचे समझे खड़े हो गए। उन्होंने यह भी सोचना जरूरी नहीं समझा कि उनके इस अपरिपक्व कार्य से देशविरोधी तत्वों को ऊर्जा मिलेगी। इससे भले ही उन्हें क्षण भर के लिए प्रचार मिल गया हो, लेकिन उनकी पार्टी की छवि दागदार हो गई। अभिव्यक्ति की आजादी की भी गलत व्याख्या की जा रही है। कांग्रेस और वामदल देशविरोधी नारे को भी बोलने की स्वतंत्रता की कसौटी पर न्यायसंगत ठहरा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इस पर संविधान ने ही तार्किक प्रतिबंध लगा रखा है, जिसका हम सभी को पालन करना अनिवार्य है। कुछ दूसरे विरोधी दल भी इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं और दोहरा आचरण कर रहे हैं, जिससे संदेश जा रहा है कि सरकार अपनी आलोचना को ही देशद्रोह मान रही है। जबकि सरकार विरोधी नारे और देश विरोधी नारे में अंतर करना बहुत आसान है। विचारों में असहमति हमारे मूल में है, लेकिन देश को तोड़ने की बातों को सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और वामदल देश में तनाव और कुछ विश्वविद्यालयों में अशांति फैलाने के असल जिम्मेदार हैं। यह न सिर्फ उनकी सोची समझी रणनीति है, बल्कि राजनीति का हिस्सा भी है। कांग्रेस को ऐसी राजनीति रास आती है और वह पार्टी और देश से पहले प्रथम परिवार के बारे में सोचती है। वहीं वाम दलों के लिए कमजोर और लचर सिस्टम उनकी अप्रासंगिक हो चुकी विचारधारा का एक अंतर्निहित हिस्सा है।

दुर्भाग्य से मीडिया के एक भाग द्वारा इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल देने से भी गलत संदेश गया। यह कहना गलत होगा कि जेएनयू की घटना का देश के छात्रों पर व्यापक असर नहीं हुआ होगा। जेएनयू वाम विचारधारा का गढ़ है। साठ साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस का अकादमिक-सांस्कृतिक संस्थानों पर एकाधिकार रहा। उस दौरान वाम बुद्धिजीवी मलाई खाते रहे। वे अब भी चाहते हैं कि इन संस्थानों पर उनका वर्चस्व बरकरार रहे। कांग्रेस और वामदल, दोनों अपने विरोध को सुनना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने विरोधी मतों को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए वे असहिष्णुता पर हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अपने विचार दूसरों पर निर्ममता से थोपना चाहते हैं। रोहित वेमुला की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या को रणनीति के तहत मुद्दा बना दिया गया

कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय में देशविरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में बिना सोचे समझे खड़े हो गए। उन्होंने यह भी सोचना जरूरी नहीं समझा कि उनके इस अपरिपक्व कार्य से देशविरोधी तत्वों को ऊर्जा मिलेगी। इससे भले ही उन्हें क्षण भर के लिए प्रचार मिल गया हो, लेकिन उनकी पार्टी की छवि दागदार हो गई। अभिव्यक्ति की आजादी की भी गलत व्याख्या की जा रही है। कांग्रेस और वामदल देशविरोधी नारे को भी बोलने की स्वतंत्रता की कसौटी पर न्यायसंगत ठहरा रहे हैं।

और इसके जरिये केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय सहित कुछ नेताओं की छवि को दागदार बनाने का प्रयास किया गया। इसमें कोई दो मत नहीं रोहित की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे देश ने एक होनहार स्कॉलर को खो दिया। आत्महत्या की खबर चौंकाने वाली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा इसे सियासत का मुद्दा बनाने की थी। पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने कैसे एक छात्र की आत्महत्या को अपने राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

कम्युनिस्ट पार्टियां अपने कामों से लोगों का दिल नहीं जीत सकीं तो कुछ विश्वविद्यालयों में अपने संगठनों का इस्तेमाल कर देश में सामाजिक तनाव पैदा कर रही हैं।

दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी न सिर्फ उनके कदमों को सराह रही है, बल्कि उनके साथ खड़ी हो गई है। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन (एएसए) अल्ट्रा लेफ्ट का अग्रणी संगठन है और हैदराबाद विश्वविद्यालय में इसका प्रभाव है। अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने का इसका इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय की दलित स्टूडेंट यूनियन से इसका कोई मेलजोल नहीं है। पुलिस को रोहित के मृत शरीर तक जाने से रोका गया। एएसए के लोगों ने पुलिस को ब्लैकमेल कर अपनी मर्जी से कुछ लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। यह पूरी तरह सत्य है कि दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। संसद में भाजपा के सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ी जाति के सांसद हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट सच्चाई को ढ़कने का काम रहे हैं। वे हैदराबाद की घटना को राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए दलित विरोधी मामले के रूप में पेश कर रहे हैं। एएसए द्वारा याकूब मेमन के लिए आयोजित नमाजे जनाजा कार्यक्रम को आखिर किस तरह जायज ठहराया जा सकता है, जबकि वह सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार था और उसे फांसी की सजा मिली थी।

मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने अपने पत्र में किसी भी छात्र के नाम का उल्लेख नहीं किया था और न ही किसी को अतिवादी और देशविरोधी बताया था। क्षेत्र के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। उन्हें जो शिकायत मिली थी उसे आगे बढ़ाया था, जिसमें लिखा था कि विश्वविद्यालय जातिवाद, अतिवाद और देशविरोधी राजनीति का अड्डा बन गया है। उसमें विश्वविद्यालय से जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई थी।

यह झूठ फैलाया गया कि दत्तात्रेय द्वारा लिखे पत्र के कारण रोहित आत्महत्या के लिए विवश हुआ। साथ ही दुष्प्रचार किया गया कि रोहित को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी। बाद में यह पूरी तरह गलत साबित हुआ। दत्तात्रेय के पत्र में जो बातें थीं, कुछ उसी तरह की बातें कांग्रेस के सांसद वी. हनुमंत राव द्वारा लिखे पत्र भी थीं। जब कोई सांसद किसी मामले में अपनी चिंता जाहिर करता है तो संबंधित विश्वविद्यालय तक उनकी बातों को पहुंचाना मानव संसाधन मंत्रालय के नौकरशाहों की दैनिक प्रक्रिया है। यही नहीं कांग्रेस के कार्यकाल में एचसीयू से कई छात्र निष्कासित या निलंबित किए गए हैं।

संप्रग के दस वर्ष के शासनकाल में दस छात्रों ने आत्महत्या की, तब न तो राहुल गांधी और न ही माकपा नेता सीताराम येचुरी ने विश्वविद्यालय जाना जरूरी समझा। जेएनयू में भगवान राम का पुतला दहन, दुर्गा की निंदा में पर्चे बांटना, महिषासुर और अफजल के गुणगान का आखिर कोई किस तरह समर्थन कर सकता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू में लगे नारे एक ही तरह के थे।

यह जांच का विषय है कि देशविरोधी तत्वों के निशाने पर सीधे-साधे छात्र तो नहीं हैं। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सतत सजगता ही स्वतंत्रता कायम रखती है। ■

(लेखक केंद्रीय संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री हैं)

संप्रग के दस वर्ष के शासनकाल में दस छात्रों ने आत्महत्या की, तब न तो राहुल गांधी और न ही माकपा नेता सीताराम येचुरी ने विश्वविद्यालय जाना जरूरी समझा। जेएनयू में भगवान राम का पुतला दहन, दुर्गा की निंदा में पर्चे बांटना, महिषासुर और अफजल के गुणगान का आखिर कोई किस तरह समर्थन कर सकता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू में लगे नारे एक ही तरह के थे। यह जांच का विषय है कि देशविरोधी तत्वों के निशाने पर सीधे-साधे छात्र तो नहीं हैं। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सतत सजगता ही स्वतंत्रता कायम रखती है।

रेल-बजट 2016-17

यात्री रेल किराए और माल-भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी को देश का 86वां रेल बजट पेश किया । रेल बजट में यात्रियों के लिए खास बात ये रही कि इस बार श्री सुरेश प्रभु ने यात्री रेल किराए और माल भाड़े में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की। वहीं पूरे बजट में यात्री सेवाएं सुधारने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा रेल बजट में देश की जनता के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

रेलमंत्री ने चार तरह की ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। हमसफर एक्सप्रेस पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी और इनमें एसी तीसरे दर्जे की सुविधाएं होंगी। इसमें खाने की सुविधा का विकल्प भी होगा, जिसे यात्री इच्छा होने पर चुन सकते हैं। दूसरे तरह की ट्रेनों को उदय एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इसके तहत डबल-डेकर वातानुकूलित ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें मौजूदा क्षमता से लगभग 40 फीसद अधिक सीटें होंगी, ताकि अधिक-से-अधिक यात्री सफर कर सकें।

तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे भी अधिक गति से चलेंगी। इसमें विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा लंबी दूरी के लिए सुपरफास्ट अंत्योदय एक्सप्रेस में अनारक्षित डिब्बे होंगे। लम्बी दूरी की कुछ अन्य ट्रेनों में दो से चार दीनदयालु सवारी डिब्बे भी लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

इस रेल बजट में दिव्यागों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए सभी स्टेशनों को दिव्यांगों की

रेल-बजट 2016-17 के प्रमुख बिंदु

- यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं।
- 65,000 अतिरिक्त बर्थ और 17,000 बॉयो टॉयलेट लगाए जाएंगे।
- प्रस्तावित रेलों की समयबद्धता में सुधार के लिए परिचालन ऑडिट।
- 400 और स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।
- स्टेशनों का विकास सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर किया जाएगा।
- इस वित्तीय वर्ष के अंत तक समर्पित मालभाड़े गलियारे के लिए सिविल अनुबंध पूर्ण।
- ई-टिकटिंग प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए निचली बर्थ का कोटा बढ़ाया गया, 820 आरओबी/आरयूबी का निर्माण।
- परिचालन अनुपात को 90 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक किया जाएगा।
- नारगोल-हजीरा बंदरगाह संपर्क परियोजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर होगा काम।
- रेल बजट अनुमानों में 8720 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत योजना 1.21 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव।
- रेलवे के ढांचागत आधुनिकीकरण पर पांच वर्ष में 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव।
- नये वित्त वर्ष में 2800 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने का प्रस्ताव।
- उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्वी तटीय पूर्वी तटीय समर्पित मालवहन गलियारे को सरकारी निजी साझेदारी से बनाने का प्रस्ताव।
- नियमित अंतराल पर तीसरी पार्टी ऑडिट और यात्रियों से फीडबैक के आधार पर ए1 और 1 श्रेणी के स्टेशनों को दी जाएगी रैंकिंग।
- ए1 श्रेणी के हर स्टेशन पर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगले वित्त वर्ष में 5 सेंटर खोले जाएंगे।
- चुनिंदा स्टेशनों, पहुंच मार्गों और करीबी कॉलोनियों में साफ-सफाई में सुधार लाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
- अगले वित्त वर्ष में 30000 अतिरिक्त जैव-शौचालय लगाए जाएंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिला यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, चुनिंदा स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्मों पर पोर्टेबल जैव-शौचालय मुहैया करवाए जाएंगे। ■

सुविधा के अनुकूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें ए1 क्लास के स्टेशनों पर दिव्यांग के अनुकूल कम-से-कम एक शौचालय बनाए जाएंगे। व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग होगी, स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्ट्स की संख्या बढ़ेगी और नए कोचों में ब्रेल लिपि युक्त दिशा-निदेर्शों की सुविधा दी जाएगी।

बुजुर्गों के लिए नीचे की बर्थ का कोटा बढ़ाया गया है। अब प्रत्येक सवारी डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली बर्थ का कोटे को 50 प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं। इससे बुजुर्गों को हर गाड़ी में लगभग 120 निचली बर्थ की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए सवारी डिब्बे को बीच के हिस्से को उनके लिए रिजर्व किया जाएगा।

24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 182 पर महिला को मदद मिलेगी। इसके अलावा 311 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी चौकसी की व्यवस्था की गई है। बाद में सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को बारी-बारी से सीसीटीवी सर्विलांस के तहत लाने की योजना है।

बेहतर सेवाओं का प्रबंध

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यात्रियों के लिए उपलब्ध मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिनमें यात्री, मौजूदा पिक अप एंड ड्राप सेवा और व्हील चेयर सेवाओं के अलावा भुगतान आधार पर बैटरी चालित कारें, कुली सेवाएं आदि बुक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेल यात्राओं के लिए बुकिंग करते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेल द्वारा बीमा कंपनियों के साथ काम कर रही है।

श्री प्रभु ने रेल यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विश्रामालयों की बुकिंग मौजूदा न्यूनतम 12 घंटे के स्थान पर घंटे के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विश्रामालयों को आईआरसीटीसी को सौंपा जाएगा, ताकि इनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। श्री प्रभु ने कहा कि शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रेन में बच्चों के लिए खानपान के पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर शिशु आहार, गरम दूध और गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा और गाड़ियों के शौचालयों में शिशुओं के लिए चेंजिंग बोर्ड भी मुहैया कराए जाएंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के आराम में वृद्धि करने की दृष्टि से, सवारी डिब्बों के डिजाइन और लेआउट में बदलाव करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि वहन क्षमता को बढ़ाया जा सके और ऑटोमेटिक दरवाजे, बार-कोड रीडर, बायो वैक्यूम टॉयलेट, वॉटर लेवल इंडिकेटर, कूड़ेदान की व्यवस्था, एर्गोनोमिक सीटें, बेहतर साज-सज्जा, वेंडिंग मशीनें, मनोरंजन स्क्रीन, विज्ञापन के लिए एलईडी लिट बोर्ड, पी ए सिस्टम और अन्य सुविधाओं सहित नई सुख-सुविधाओं की व्यवस्था हो। इन नए स्मार्ट (स्पेशली मॉडिफाइड इस्थेटिक रीफ्रेशिंग ट्रेवल) सवारी डिब्बों से हमारे ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उच्चतर वहन क्षमता के कारण परिचालन की यूनिट लागत की कमी भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि रेलवे की मंशा अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरूपति, वेलंकन्नी, वाराणसी और वास्को जैसे धार्मिक महत्व के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण तथा यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की है। श्री प्रभु ने राज्यों से अपील की कि वे आगे आएं और पीपीपी माध्यम से सैटलाइट टर्मिनल स्थापित करने में भागीदारी करें।

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा

वर्ष 2016-17 के रेल बजट में की गई घोषणाओं से देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ उनकी लागत में कमी आएगी और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। रेल बजट में रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने फ्रेट टर्मिनल के निकट खाली पड़ी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है।

साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे स्थानीय किसान और मछुआरे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए उन्हें बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से इस बावत नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।

रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने माल ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे की फ्रेट बास्केट का विस्तार करने की बात कही है। खासकर ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों की ढुलाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे लागत में कमी आने से वाहनों की कीमत कम होगी। मालगाड़ियों को टाइम टेबल के हिसाब से चलाए जाने से उद्योगों का माल समय पर गंतव्य तक पहुंचेगा। इससे उद्योगों की लागत घटने के अलावा ग्राहक सेवा में सुधार होगा।

400 रेलवे स्टेशनों का विकास

400 रेलवे स्टेशनों का पीपीपी मॉडल के आधार पर पुनर्विकास किया जाएगा। इसके तहत, अगले वित्त वर्ष में कुछ बड़े और मझोले स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए बिडिंग का काम शुरू होगा। यात्री के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए भी प्रभु ने प्लान पेश किया।

मॉडल्स के आधार पर देश के रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। एक मॉडल के आधार पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है, जबकि चार अन्य स्टेशनों की बोली प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

यात्री सुविधा पर ध्यान

रेल बजट 2016-17 में यात्री किराया और माल भाड़े में कोई बदलाव न करते हुए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने यात्री सुविधा पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के कारण 2016-17 में हमें 92 फीसदी संचालन अनुपात रहने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में यह 90 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संचालन अनुपात का लक्ष्य 88.5 फीसदी रखा था।

श्री प्रभु ने विकास परियोजनाओं के लिए योजनागत व्यय को करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा, इस साल हमारा निवेश पिछले वर्षों के औसत का लगभग दोगुना होगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने रेलवे की कुल आय भी आगामी वित्त वर्ष में 10 फीसदी अधिक रहने की उम्मीद जताई।

श्री प्रभु ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अत्यधिक अनुकूल शर्तों पर अगले पांच साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के लिए सहमत हुआ है। हम परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए बहुपक्षीय सहयोग से एक कोष स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।

अपने बजट भाषण के दौरान रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अब तक भारतीय रेल ने राजस्व बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर ही विशेष जोर दिया है। हम इस बदलना चाहते हैं और परिवहन के क्षेत्र में हमारे हिस्से को दोबारा पाने के लिए हम मालभाड़ा नीतियों पर अपनी परंगरागत सोच को बदलना चाहते हैं। हम राजस्व के नए स्त्रोतों का दोहन करेंगे ताकि प्रत्येक दृश्य या अदृश्य परिसंपत्ति को अधिकाधिक भुनाया जा सके। अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए खर्च होने वाले एक-एक रुपए की फिर से जांच की जाएगी। हम आगामी वर्ष में वित्तीय दृष्टि से शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की अवधारणा अपनाएंगे। हम अपने कार्यकुशलता के मानदंडों और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार करके उन्हें अंतराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के समकक्ष बनाएंगे। हम अपने प्रत्येक क्रिया-कलाप को कुशलता से पूरा करेंगे और परिणाम भी प्राप्त करेंगे।

2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकट

2020 तक सभी यात्रियों के लिए जब चाहें टिकट की व्यवस्था की जाएगी, यानी यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी और सभी को कंन्फर्म टिकट टिकट मिलेगा। 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्री ट्रेन की औसत स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जाएगा। इसके साथ ही 2020 तक 95 प्रतिशत ट्रेनें समय से चलाने का भी लक्ष्य रखा है। ■

टिप्पणी

रेल बजट का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत रेल बजट की सराहना की और हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करनेवाली एक सर्व समावेशी यात्री फ्रेंडली रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की ओर से बहुत - बहुत बधाई दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी विकासोन्मुखी और आम आदमी की सुविधाओं पर केंद्रित रेल बजट के लिए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, रेल परिवार और टीम रेल को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के नवनिर्माण में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस रेल बजट का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा और यह देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खर्च में अनुशासन, प्रबंधन में दक्षता एवं उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही, इस रेल बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन से नहीं, कमीशनिंग से पारिभाषित किया गया है जो सोच में एक पैराडाइन शिफ्ट को दर्शाता है। ■

कांग्रेस को राजनीति करनी है तो चुनावी मैदान में आए : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 मार्च को आंध्र प्रदेश के राजमहेन्द्रवरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने आंध्र के विकास के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का ब्यौरा दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ-बूथ पर जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। श्री शाह ने आंध्र प्रदेश की 25 में से 17 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जिताने के लिए जनता का आभार भी जताया।

श्री शाह ने कहा कि हमारे विरोधी डेढ़ साल से एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार हैं, वे दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की दोनों सरकारें यहां पर विकास नहीं होने देती हैं। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने डेड़ साल में आंध्र प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं दी हैं।

श्री शाह ने पोलावरम परियोजना पर कांग्रेस से सवाल किया कि जब कानून बना तब किसकी सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर भाजपा कानून में संशोधन नहीं करती तो पोलावरम परियोजना असंभव थी। आज पोलावरम पूरा हो रहा है तो इसलिए कि नरेन्द्र मोदी ने कानून में संशोधन किया। इसलिए यह परियोजना पूरी हो रही है। पोलावरम को केंद्रीय परियोजना घोषित करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।

श्री शाह ने कहा कि पोलावरम परियोजना पूरे आंध्र प्रदेश की जीवन-रेखा है। इसके लिए जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार करने को तैयार है। अगर कोई यह समझता है कि पूरी परियोजना के पैसे एक ही बजट में या एक ही साल में जारी कर दिए जाएं तो वह जनता को गुमराह कर रहा है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली देने को पायलट परियोजना के लिए चयन किया है। आंध्र प्रदेश के नेशनल हाइवे के लिए 6,500 करोड़ रुपये, अंतर-राज्यीय जल मार्ग के लिए 1,500 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 37 शहरों में एक लाख 93 हजार लोगों के लिए घर बनाने को मोदी सरकार ने धनराशि दी है। अमृत योजना के लिए आंध्र प्रदेश के 31 शहरों का चयन किया है जो देश में सबसे ज्यादा हैं। काकीनाडा और विशाखापत्तनम का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है। अमरावती में नई राजधानी के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपये, नेल्लोमर में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से कृभको कारखाना और कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, 22,000 करोड़ रुपये की लागत से आंध्र प्रदेश में औद्योगिक पार्क लगाने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने 3,266 करोड़ रुपये की लागत से नेवल-एयर स्टेशन आंध्र प्रदेश में बनाने, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर और डिफेंस सीक्युरिटी स्टांफ ट्रेनिंग के लिए भी आंध्र प्रदेश का चयन किया गया है। गुंटूर में 1,616 करोड़ रुपये से एम्स, विशाखापत्तनम में 25,000 करोड़ रुपये से एचपीसीएल की रिफाइनरी, वियजनगरम में आदिवासी विश्व विद्यालय, अनंतपुरम में केंद्रीय विश्वविद्यालय और विशाखापत्तनम में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चयन किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए सीपीआर का प्रोजेक्ट अलग से मंजूर किया गया है।

श्री शाह ने लोगों से कहा कि वह आश्वस्त करते हैं कि मोदी सरकार जब तक है आंध्र का गौरव हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा और आंध्र को कोई भी अपमानित नहीं कर पाएगा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ आगे बढ़ रही है।■

बरेली (उप्र) में किसान रैली

जन का पोषक है किसान : मोदी

हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है।'' यह बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित किसान रैली में कहीं। श्री मोदी ने कहा कि देश में किसानों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। परिवार बंटते जा रहे हैं। जमीन भी बंट रही है।

विरासत में किसान जमीन बांट भी पाएगा कह पाना मुश्किल है। जमीन कम हो जाती है तो पैदावर कम हो जाती है। इन चुनौतियों का समाधान नहीं है। यदि किसान साथ दें और राज्य सरकारें तैयार हों तो कृषि विभाग केंद्र के हवाले हो। खेती व किसान के लिए ऐसा होना जरूरी। कृषि पूरी तरह केंद्र के पास नहीं है। राज्य सरकार के हाथ में भी काफी कुछ है। ईश्वर के बाद किसानों की कोई मदद नहीं करता। राज्य सरकारें किसानों व कृषि को प्राथमिकता में लें।

मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को बल्कि सभी राज्य की सरकारों से अनुरोध करता हूं कि अपने राज्य के कामों में किसानों को वरीयता दें।

अगर हमने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लागू करने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें तो हमारा सपना पूरा हो सकता है। हम प्रण कर लें कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर दें जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा। यह इतना कठिन काम नहीं है।

मध्य प्रदेश का नाम कभी भी कृषि के अव्वल प्रदेशों में नाम नहीं था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम आता था। जब वहां भाजपा की सरकार बनी और विशेषकर श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लेकर कृषि को प्राथमिकता दी।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाएं बनाई, बूंद-बूंद पानी का प्रयोग किया। आज पिछले तीन साल से मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नंबर वन राज्य है।

मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया। मैं तो यहां आया हूं आग्रह करने। भारत की केंद्र सरकार कृषकों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तीन स्तम्भों की जरूरत है। अर्थरचना में एक तिहाई हिस्सा कृषि का है, एक तिहाई हिस्सा उद्योगों का और एक तिहाई हिस्सा सर्विस सेक्टर का है।

आज किसान मां-बाप चाहता है कि एक बेटा ही किसानी करे। बाकी सभी बेटे घर से बाहर निकलकर रोजगार के लिए जाएं। खेती को भी तीन हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। पहली, उपज प्राप्त करें। दूसरी, किसान खेतों के अंतिम छोर पर टिम्बर की खेती करें। संकट में यह पेड़ उनका संकटमोचक बनेगा। एक मीटर जमीन हर किसान खराब कर देता है, उसमें बाड़ लगा देता है। अगर इन सीमाओं का प्रयोग वृक्ष लगाने के लिए करें तो 15-20 साल में पेड़ तैयार हो जाएंगे। घर में बेटी हो तो एक पेड़ लगा दें। जब तक बेटी जवान होगी पेड़ भी बड़ा हो जाएगा। उस पेड़ का प्रयोग बेटी की शादी के लिए किया जा सकता है।

तीसरे हिस्से में जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करें। किसान मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। अगर हम पशुपालन पर ध्यान दें तो यह प्रकृति रूठ जाए तब भी काम आ सकता है। पिछले साल हमारे देश में सबसे ज्यादा अंडे की पैदावर हुई है और इसका फायदा ग्रामीण भाइयों को हुआ है।

हमारे देश में खेती को मजबूती देने की जरूरत है। सिर्फ किसाने के जेब में रुपए डालने से बात नहीं बनेगी।

बुंदेलखंड की हालत देखकर मुझे चिंता होती है। जिस क्षेत्र में पांच नदियां हों वहां के लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं हैं। किसान को समय पर

पानी मिल जाए तो वो मिट्टी से सोना निकाल सकते हैं।

अटलजी का सपना था सभी नदियों को जोड़ने का। अगर वह सपना पूरा हो जाता तो बाढ़ से भी बचते और सूखे से भी। पचास हजार करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। मनरेगा के पैसों से सिंचाई के प्रबंध मजबूत किया जाना चाहिए।

नहर, तालाब आदि को सुदृढ़ किया जाए। संसाधन मजबूत करके गांव का पानी गांव में ही रह जाएगा तो सूखे का संकट नहीं होगा। खेती के लिए पानी के संकट को भी दूर करने की जरूरत है ताकि खेती बर्बाद न हो।

हमने 50 हजार करोड़ की लागत से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करने का जिम्मा उठाया।

मनरेगा में क्या हुआ हम नहीं जानते। गांव में जाकर पूछो - मनरेगा में क्या काम हुआ, किसी को पता नहीं। इससे यह पता चलता है कि पिछली सरकार ने मनरेगा कैसे चलाया

हम भी संकल्प कर लें कि पानी की एक-एक बूंद का प्रयोग करेंगे। गांव के नौजवानों बारिश के पानी को रोकने के लिए कोशिश कर लो तो साल भर में सभी कुओं की जरूरत का पानी जमा हो जाएगा।

बिना समझे फर्टिलाइजर व कीटनाशक का प्रयोग न करें। इससे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। हम किसान के बेटे हैं, हमें धरती मां पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक दवा दी जाए तो वह नुकसान करती है। हमने धरती मां पर कितना अत्याचार किया।

अटलजी का सपना था सभी नदियों को जोड़ने का। अगर वह सपना पूरा हो जाता तो बाढ़ से भी बचते और सूखे से भी। पचास हजार करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। मनरेगा के पैसों से सिंचाई के प्रबंध मजबूत किया जाना चाहिए।

अनाप-शनाप दवाइयों के प्रयोग के कारण हमारी धरती मां बीमार हो गई।

बहुत बड़ी मात्रा में हमारे राधामोहन सिंह जी ने जमीन की रक्षा के लिए अभियान चलाया है।

मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। इससे अधिक उपज मिलेगा। सरकार का देश के गांव-गांव तक मृदा परीक्षण लैब पहुंचाने का इरादा है।

बीज भी खेती में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार ने उत्तम से उत्तम बीज पहुंचाने के लिए कोशिश की है। सस्ते में किसान तक बीज पहुंचाने के लिए हमारी योजना है।

मुख्यमंत्रियों की पहले चिट्ठी आती थी कि भारत सरकार यूरिया दे। इस बार एक भी मुख्यमंत्री ने यूरिया के लिए भारत सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी।

इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के कई एमपी मिलते हैं। कहते हैं पहले तो हमारे यहां यूरिया लेने के लिए खेत छोड़कर कतार में लगना पड़ता था। कभी-कभी यूरिया नहीं आती थी तो पुलिस लाठी चार्ज करती थी।

सरकार ने यूरिया का नीमकोटिंग कराने का काम किया। अगर आपके खेत में 10 किलो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो 3 किलो कम डालने की जरूरत पड़ती है। देश की सरकार ने 100 फीसदी नीमकोटिंग किया है।

तीसरा एक काम हुआ, केमिकल के लिए जो फर्टिलाइजर्स चला जाता था, वो बंद हो गया। इस वजह से यूरिया की कालाबाजारी बंद हो गई। इसके अलावा लोगों को नीम के बीज एकत्र करने के कारण रोजगार भी मिल रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने किसान को सुरक्षा देने के लिए लागू किया है। हमने कोशिश की है कि 100 में से कम से कम 50 किसान फसल बीमा योजना लें।

मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप फसल बीमा योजना जरूर लें। जितने अधिक किसान फसल बीमा योजना लेंगे, दिल्ली के खजाने से उसका उतना अधिक पैसा जाएगा लेकिन मुझे किसानों की भलाई करनी है।

आपके खेत में ओले गिर गए, भूस्खलन हो गया। अगर किसी एक किसान के खेत को नुकसान होगा तो उसे भी फसल बीमा का पैसा मिलेगा।

हमने कृषि में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। किसान को अब बारिश के भरोसे बैठे नहीं रहना होगा। पहली बार देश ने तय किया है कि अगर बारिश नहीं हुई और बुआई नहीं हो सकी तो उसका भी लाभ फसल बीमा में होगा। इस सरकार ने निर्णय किया कि अगर फसल कटने के 14 दिन के भीतर प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसको भी बीमा से राशि दी जाएगी।

कृषि जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम चल रहा है। राज्य सरकारें भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम करें। ■

कार्यकर्ता सम्मेलन, गांधी नगर (गुजरात)

गुजरात भाजपा का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दिनांक 27 फरवरी 2016 को गुजरात के गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया और अपने भव्य स्वागत और सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा 1950 में जनसंघ के रूप में मात्र 11 सदस्यों के साथ शुरू हुई थी और आज 11 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जो अद्‌भुत और अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि हमारी अब तक की यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, वैचारिक यात्रा रही है। श्री शाह ने कहा कि जनसंघ की स्थापना के वक्त तो हमने सपने में भी सत्ता नहीं सोची थी लेकिन आज 13 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और यही नहीं, केंद्र में भी देश की जनता ने अपना पूर्ण बहुमत देकर देश सेवा की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और भाजपा एकमात्र ऐसी गैर-कांग्रेसी पार्टी है जिसे आजादी के बाद अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला है।

कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत और भारतवासियों का मान - सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 'सबका साथ - सबका विकास' के सिद्धांत पर काम करते हुए गाँवों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के सर्वांगीण विकास एवं उनके कल्याण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की हरेक योजनाएँ चाहे वह जन - धन योजना हो, जीवन बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, मुद्रा योजना हो, मेक इन इंडिया कैंपेन हो, स्टार्ट-अप इंडिया कैंपेन हो, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना हो, नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी हो या फिर डिजिटल इंडिया योजना हो - सभी योजनाएं गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए ही समर्पित हैं।

गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यहां के कार्यकर्ता विचारधारा की राजनीति करते हैं और नि:स्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ते, वह देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए लड़ते हैं, इतिहास इसका गवाह है, चाहे गोवा मुक्ति अभियान हो, कच्छ बचाओ आंदोलन हो, हैदराबाद को भारत में विलय करने का अभियान हो, कश्मीर बचाओ आंदोलन हो, देश की एकता के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हो, चेतना यात्रा हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो या फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभियान हो।

श्री शाह ने कहा कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जन - जन के आशीर्वाद से अपने लगातार विजय की स्वर्ण जयंती अवश्य मनाएगी। श्री शाह ने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार अंगद के पांव की तरह है, हताश और निराश कांग्रेस इसे डिगा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात को एक आदर्श वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गुजरात से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मेरे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी और मैं आज जिस मुकाम पर हूं, वह गुजरात की वजह से ही हूँ। उन्होंने कहा - 'गुजरात भाजपा का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा।' श्री शाह ने कहा कि हम गुजरात की जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि विजय आपकी राह देख रही है, लक्ष्य आपका इन्तजार कर रहा है, आप राज्य और देश के विकास के लिए एकजुट हो जायें और राज्य में फिर से भाजपा की सरकार को लाने का दृढ़ निश्चय कर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जायें। ■